

प्रेषक,

कुँवर सिंह,

अपर सचिव,

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उत्तरांचल पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम,

देहरादून।

पेयजल अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 18 सितम्बर 2006

विषय: ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चौखुटिया पुनर्गठन पेयजल योजना की वित्तीय स्वीकृति। महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 904/उन्तीस(2)/05-2(03पे0)/2004, दिनांक 27.10.2005 के द्वारा जनपद अल्मोड़ा में चौखुटिया पुनर्गठन पेयजल योजना के ₹0 153.90 लाख की लागत के आगमन पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रश्नगत योजना पर शासनादेश संख्या 1420/उन्तीस/4/02-(03पे0)/2003, दिनांक 18.09.04 द्वारा ₹0 25.00 लाख तथा शासनादेश संख्या 356/उन्तीस/5/02-(19पे0)/2004 दिनांक 05.03.2005 के द्वारा ₹0 88.05 लाख अर्थात् कुल ₹0 113.05 लाख (₹0 एक करोड़ तेरह लाख पाँच हजार मात्र) की स्वीकृति पूर्व में जारी की जा चुकी है। इस प्रकार योजना हेतु ₹0 40.85 लाख की धनराशि अवमुक्त की जानी शेष है। अतः इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उपरोक्त उल्लिखित शासनादेश संख्या 904, दिनांक 27.10.05 में निर्धारित शर्तों के अधीन ₹0 40.85 लाख (₹0 चालीस लाख पिच्चासी हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर के अंतर्गत आपके निर्वहन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके, आवश्यकतानुसार किस्तों में आहरित की जायेगी तथा आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या व दिनांक की सूचना महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून तथा शासन को तुरन्त उपलब्ध करा दी जायेगी।

3 स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.12.2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

4-चूँकि अब पुनरीक्षित आगणन के विपरीत समस्त अवशेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। अतः किन्हीं भी कारणों से इसकी लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

5-योजना पर पूर्व में अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि के उपभोग के पश्चात ही अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण किया जायेगा।

6-उक्त योजना पर व्यय करने के सम्बंध में उपर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 05 अक्टूबर, 2005 के अनुरार रहेंगी

7-उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में अनुदान सं०-13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जलापूर्ति- आयोजनागत -102- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-03-ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता के नामे" डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं०-534/xxvii(2)/2005 दिनांक 12 सितम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)

अपर सचिव

पु०सं० 1527 / उत्तीस(2)-2(03पे०)/2004, तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून।
2. मण्डलायुक्त कुमाँयू।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान।
6. वित्त अनुभाग-2/वित्त(बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल।
7. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तरांचल।
8. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
9. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
- ✓ 10. निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)

उप सचिव